www.deshkiupasana.com
राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र
RNI NO - UPHIN/2022/86937
जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE
सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 256 | जौनपुर बुधवार, 06 मई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

मोदी मैजिक’ के आगे बंगाल का ‘काला जादू’ हुआ फेल

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का सबसे अहम कारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभावशाली नेतृत्व रहा। उनकी बात बंगाल की जनता के दिलों तक पहुंची, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिला। इसके साथ ही राज्य में पार्टी के तेज–तर्रार नेताओं द्वारा लगातार की गई चुनावी सभाओं ने भी माहौल को भाजपा के पक्ष में मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल में प्रचलित तथाकथित ‘काला जादू’ जैसी ध ारणाओं से ऊपर उठकर जनता ने विकास और नेतृत्व के मुद्दों पर ध यान केंद्रित किया। परिणामस्वरूप, मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर हुआ, जो चुनाव परिणामों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। वैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा की इस जीत के लिए जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने कमर कसी, उतनी ही शिद्दत से पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में हवा का रूख तैयार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मेहनत की। वैसे भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में राजनीति की उपजाऊ जमीन तैयार करने के काम पार्टी की तरफ से बहुत पहले शुरू कर दिया गया था। नरेंद्र कप (फुटबॉल टूर्नामेंट) का आयोजन यहां किया गया था। इस पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट में 1200 टीमों ने भाग लिया और लगभग 18,000 खिलाड़ी सम्मिलित हुए। वहीं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 253 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। दोनों ही आयोजनों में 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा सम्मिलित हुए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाने जाने वाले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान पदयात्रा, पुष्पांजलि, तिरंगा वितरण, सामूहिक गायन तथा दीप प्रज्वलन जैसे आयोजन हुए। इसमें 1 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए। यहां राज्य भर में भाजपा की तरफ से 9 परिवर्तन यात्रा आयोजित हुई। जिसमें 294 में से यहां के कुल 217 विधानसभा क्षेत्र कवर हुए। कुल 560 बड़े एवं छोटे कार्यक्रम में लगभग 7 लाख से अधिक लोग इससे जुड़े। इसके साथ ही भाजपा ने यहां बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया। यहां

70,671 बूथों पर बूथ समितियां बनाई गई एवं अन्य पर बूथ अध्यक्ष बनाए गए। इन बूथ समितियों पर 8,76,765 कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। साथ ही वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव एवं वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के आधार पर 210 फोकस विधान सभाएं चिह्नित की गई। इसके साथ ही इसमें से सभी बूथों का विश्लेषण कर फोकस बूथ चिह्नित किए गए। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की विफलताओं एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राज्य स्तरीय आरोप–पत्र जारी किए। विधानसभा स्तर पर 220 विधानसभा क्षेत्रों में यह चार्जशीट जारी की गई। ताकि जनता इसके बारे में जान सके। पूरे बंगाल में महिला एवं युवा वर्ग के 2 करोड़ से अधिक भरोसा कार्ड भरे गए। महिलाओं के लगभग 1.60 करोड़ एवं युवाओं के 40 लाख फॉर्म भरवाए गए। श्रीरामनवमी, श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं पोइला बैसाख के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 6,250 स्थानों पर धार्मिक एवं आध यात्मिक संगठनों के प्रमुखों से संपर्क किया गया। 2 लाख से अधिक लोगों से इस दौरान संपर्क साधा गया। इसके साथ ही 21 प्रदेशों से 9,498 बंगाली प्रवासियों ने पश्चिम बंगाल आकर भाजपा के पक्ष में प्रचार में भाग लिया। प्रदेश भर में 8,315 शक्ति केंद्र पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। इसके साथ ही 220 विधानसभाओं में रोजगार चाहने वाले युवाओं का पंजीकरण करने का अभियान ‘चाकरी चाई बांग्ला’ चलाया गया। महिलाओं को भाजपा ने अपने पक्ष में करने के लिए बूथ पर महिलाओं की 1,96,000 ड्रॉइंग रूम बैठकें आयोजित की। साथ ही 19,250 क्लब एवं एनजीओ के सदस्यों से संपर्क किया गया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान 61 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेताओं के 288 सीटों पर 600 से अधि क कार्यक्रम हुए। भाजपा की तरफ से यहां ‘ब्रिगेड चलो’ विशाल जनसभा कोलकाता में हुई, जिसमें 7.5 लाख लोगों की उपस्थिति रही। सोशल मीडिया पर भी इसको खूब प्रचारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कुल 19 चुनावी सभाएं हुई ।

संक्षिप्त खबरें

आखिर कैसे पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी

बिहार, (एजेंसी)। अंग यानी बिहार और कलिंग यानी ओडिशा का मोर्चा तो बीजेपी ने पहले ही फतह कर लिया था. अब बंगाल में चुनावी जीत के साथ ही अंग, बंग और कलिंग पर काबिज होने का भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हो गया है. इस बार के विधानसभा चुनाव में मुकाबला बदला बनाम श्बदलावश था. बीजेपी ने जहां बदलाव का नारा देते हुए अपने पारंपरिक श्जय श्री रामश की जगह जय मां काली के नारे को अपनाया था, वहीं ममता बनर्जी ने लोगों से केंद्र, बीजेपी और चुनाव आयोग के कथित सौतेले रवैए के खिलाफ बदला लेने के लिए वोट डालने की अपील की थीपश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में कई चीजें पहली बार हुई थीं और इसका नतीजा भी पहली बार बीजेपी की जीत के तौर पर सामने आया है. बीते पच्चीस वर्षों में पहली बार कोई चुनाव दो चरणों में कराया गया है. इससे पहले छह से आठ चरणों में मतदान कराया जाता रहा है. इसके अलावा भारी तादाद में तैनात केंद्रीय बल, और एसआईआर के दौरान कटे करीब 91 लाख नामों में राजनीतिक दलों के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं बंगाल में बीते कई दशकों में पहली बार चुनावी हिंसा न के बराबर हुई है. इससे पहले, यहां पर चुनाव से पहले और बाद में भारी हिंसा होती रही हैइस बार राज्य में पहली बार रिकार्डतोड़ वोट पड़े थे. उसके बाद से ही सत्ता के दावेदार अपने–अपने तरीके से इसकी व्याख्या करने में जुटे थे. इस बार चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है।

अमित शाह से योगी तक, मनोहर लाल को जन्मदिन पर नेताओं ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत देश के कई वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र में योगदान की सराहना की। साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ष्केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में आप आवास, शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मनोहर लाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, ष्केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को जन्मदिन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वे भारत में नगरीय सुविधाओं को विकसित करने एवं देश के ऊर्जा क्षेत्र को और भी मजबूत करने के लिए, जिस कर्मठता और पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं, वह प्रसंशनीय है।

शिक्षामित्र के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी– संवाद से समाधान, टकराव से नहीं

गोरखपुर, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिक्षामित्र सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय बढ़ोतरी के फैसले को सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण बताते हुए शिक्षामित्रों को सकारात्मक सोच और जिम्मेदारी के साथ काम करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि संवाद के जरिए समाधान संभव है, जबकि टकराव की राजनीति समाज और शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार को गोरखपुर में आयोजित शिक्षामित्र सम्मान समारोह में कहा कि वर्षों से लंबित मांगों को

उनकी सरकार ने संवेदनशीलता के साथ हल किया है, लेकिन इसके लिए टकराव नहीं, बल्कि संवाद का रास्ता अपनाना जरूरी है। सीएम योगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक बनाने का प्रयास किया, जो विधि विरुद्ध था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों की सेवाएं समाप्त होने का संकट खड़ा हो गया था। उनकी सरकार के सामने डेढ़ लाख परिवारों के सामने रोजी–रोटी का गंभीर संकट था। उन्होंने आगे बताया कि उनकी सरकार ने 2017 में शिक्षामित्रों की सेवाएं समाप्त करने के बजाय उन्हें बनाए रखने का निर्णय लिया और उनका मानदेय 3,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार समय–समय पर मानदेय बढ़ाने की इच्छुक थी, लेकिन कुछ लोगों ने शिक्षामित्रों के बीच भ्रम और शोषण की स्थिति पैदा की। मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों को संबोधित करते हुए।

पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अर्पित की पुष्पांजलि

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर मंगलवार को देशभर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। ज्ञानी जैल सिंह का जीवन देशभक्ति, सादगी और जनसेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण माना जाता है। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बताया गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कई नेताओं ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर

पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी बताते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा और लोकतंत्र के प्रति उनका समर्पण हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी उन्हें याद करते हुए लिखा, "भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्व. ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। उनका जीवन राष्ट्रसेवा, सादगी और जनसमर्पण का अद्भुत उदाहरण है, जो हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।" राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी उन्हें कोटि–कोटि नमन किया। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा, "भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती पर कोटि–कोटि नमन। एक स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर जननेता और देश के 7वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सदैव राष्ट्रसेवा, सामाजिक समरसता और जनकल्याण को सर्वोपरि रखा। साध ारण पृष्ठभूमि से उठकर सर्वोच्च पद तक पहुंचने का उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सादगी का प्रेरक उदाहरण है। देश की एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा सदैव स्मरणीय रहेगी। उनकी विरासत हमें निरंतर राष्ट्रसेवा के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है।

राघव चड्ढा ने राष्ट्रपति से की पंजाब सरकार की शिकायत, कहा- एजेंसियों के जरिए लिया जा रहा बदला

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी (आप) और पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्आपश की पंजाब सरकार राज्य की मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और विरोध करने वाले नेताओं को निशाना बना रही है। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि उन्होंने तीन अन्य सांसदों के साथ भारत की राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि आप की पंजाब सरकार उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, खासकर तब जब दो–तिहाई सांसदों

ने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा कि जिस पार्टी ने कभी बदले की राजनीति का आरोप लगाया था, वही अब सबसे विषैला रूप अपनाकर बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें आश्वस्त किया है कि संवैध ानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक फैसलों का सम्मान होना चाहिए। राघव चड्ढा ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि आज पार्टी किसी राजनीतिक संगठन की तरह नहीं, बल्कि एक नाराज और आहत पूर्व साथी की तरह व्यवहार कर रही है, जो कड़वाहट और बदले की भावना से भरी हुई है। वहीं, दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान भी उन्होंने श्आपश पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ष्मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहता हूं कि पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, वह बहुत खतरनाक खेल है। जब तक हम आपके साथ थे, तब सब ठीक था, और अब अलग हो गए तो हम भ्रष्ट हो गए? उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार की एजेंसियों और सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी अब भ्रष्ट लोगों के हाथों में है। उन्होंने यह भी कहा कि आप के पास सिर्फ एक राज्य की सरकार और पुलिस है, जबकि भाजपा के पास 21 राज्यों में सरकारें और उनकी पुलिस है।

पश्चिम बंगाल और असम में जनता का भरोसा उपलब्धि नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है : धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधान चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी के मजबूत प्रदर्शन और जनसमर्थन पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं सभी पांच राज्यों के मतदाताओं को हार्दिक बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। अपना वोट डालकर उन्होंने अपनी पसंद व्यक्त की है और अपनी पसंदीदा सरकारें चुनी हैं। यही लोकतंत्र का सार और हमारी संवैधानिक व्यवस्था का मूल सिद्धांत है।" पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन पर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "मैं इसे उपलब्धि नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी मानता हूं। लोकतंत्र में जब लोग बार–बार अपना विश्वास जताते हैं तो वह पार्टी पर भरोसा करते हुए जिम्मेदारी देते हैं। आज 22 से अधिक राज्यों में एनडीए और भाजपा की सरकारें हैं। प्रध ानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीन कार्यकालों से हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं।"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "यह हताशा और हार की भाषा है। अगर ममता बनर्जी को नैतिकता और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास है तो उन्हें हार को शालीनता से स्वीकार कर लेना चाहिए। जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा, "आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, "बादल छटेंगे, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज पूरे देश में कमल खिल रहा है। पश्चिम बंगाल में पहली बार हमारी सरकार बनने जा रही है।

बंगाल चुनाव में `विकास और सुशासन के पक्ष में जनादेश´ : मुख्यमंत्री धामी

देहरादून, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों को विकास की रफ्तार को चुनने वाला ऐतिहासिक जनादेश बताते हुए बंगाल की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बध ाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा है कि, पश्चिम बंगाल की जनता ने भय, तुष्टिकरण और अव्यवस्था को नकारते हुए विकास, सुशासन और राष्ट्रहित के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की जनकल्याणकारी नीतियों पर

जनता के विश्वास का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लिखा कि यह जीत केंद्र और राज्य में श्डबल इंजन सरकारश की अवधारणा को और मजबूती देगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि यह परिणाम भाजपा के अंत्योदय के संकल्प और सुशासन के मॉडल की स्वीकार्यता को दर्शाता है। भाजपा नेतृत्व की ओर से भी इस जीत को संगठनात्मक मजबूती और रणनीतिक नेतृत्व का परिणाम बताया गया। उन्होंने बयान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के भरोसे ने यह सफलता दिलाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर उनकी मेहनत ने भाजपा को यह सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में राज्य में विकास, सुरक्षा और सुशासन के नए आयाम स्थापित होंगे।

यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को राहत– प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड की तरह काम करेंगे

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में कार्य करेंगे। पहले की तरह ही बिजली बिल में बिल जमा करने की तिथि उल्लिखित रहेगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना बकाया भुगतान 10 किस्तों में करने की बड़ी राहत भी दी गई है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री एके शर्मा ने इस संबंध में बैठक के बाद विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिलिंग साइकिल वैसे ही रहेगा जैसे पहले पोस्टपेड मीटर में होता था।

पूर्व की तरह 1 तारीख से माह के अंत तक बिल की खपत का एक महीने का बिल एसएमएस और व्हाट्सएप पर दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बदला है, वे अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। इस फैसले से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिलिंग प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिल मिल जायेंगे। बिल मिलने की तिथि से भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। जिस उपभोक्ता को समय से बिल न प्राप्त हो वो व्हाट्सएप चौटबॉट्स पर संयोजन संख्या सूचित कर अपना बिल व बकाया बिल प्राप्त कर सकेंगे। यह बिल 1912 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर भी प्राप्त किए जा सकेंगे। उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए यह बड़ा निर्णय लिया गया है कि 30 अप्रैल तक (मई के बिल से पूर्व) उपभोक्ता का जो भी बिल बकाया रहेगा, वह 10 किस्तों में जमा कर सकता है। यदि किसी उपभोक्ता को बिल सम्बन्धी कोई समस्या है तो खण्ड एवं उपखण्ड स्तर पर मई एवं जून माह में वृहद् कैम्प का आयोजन कर स्मार्ट मीटर बिल सम्बन्धित शिकायत निस्तारण की सुविधा दी जाएगी। उपभोक्ता अपनी शिकायत 1912 पोर्टल पर भी दर्ज कर सकता है।

संपादकीय

मजदूरों के असंतोष

नोएडा में कारखाना मजदूर सड़क पर उतरे। वहां की घटनाओं ने उन हालात की ओर ध्यान खींचा, जिससे हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर आंदोलित हुए हैं। मजदूरों के असंतोष पर सहानुभूति से ध्यान दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा में मजदूरों का उबलता असंतोष सोमवार को सड़कों पर छलक गया। हिंसा, आगजनी और पुलिस कार्रवाई ने वहां उन हालात की ओर ध्यान खींचा, जिस कारण हाल में देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर आंदोलित हुए हैं। वैसे, तो इन आंदोलनों के स्थल देश भर में फैले हुए हैं, लेकिन खास चर्चा हरियाणा में हुई आंदोलनकारी गतिविधियों की हुई। आखिरकार उनका असर हुआ, और हरियाणा सरकार ने आठ अप्रैल को सभी श्रेणियों के कर्मियों की न्यूनतम मजदूरी में 35 प्रतिशत बढ़ोतरी का एलान किया। इस निर्णय का असर नोएडा में देखा गया। कुछ ही दूरी पर एक जैसे काम के लिए अलग–अलग मजदूरी की बात उन्हें चुभी और वे भी आंदोलन पर उतर आए। वैसे भी एक विश्लेषण के मुताबिक 2016 से अब तक दिल्ली और हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी काफी कम बढ़ी है। दिल्ली में ये वृद्धि लगभग 90 फीसदी और हरियाणा में 89 प्रतिशत रही, जबकि उत्तर प्रदेश में इसमें महज 42.6 फीसदी का इजाफा हुआ है। यानी गुजरे एक दशक में हुई मुद्रास्फीति के अनुपात में यूपी में मजदूरी नहीं बढ़ी है। ऐसे में मजदूरों के असंतोष को समझा जा सकता है। इस बीच श्रम कानूनों की जगह श्रम संहिताएं लागू होने और आठ घंटे काम की सीमा हटाए जाने की वजह से मजदूर पहले मिली वैधानिक सुरक्षाओं से वंचित हो गए हैं। उनकी पीड़ा को एक मजदूर की एक टीवी चौनल पर कही गई इस बात से समझा जा सकता है कि रोजाना 12 घंटे काम करने के बाद उन्हें महीने में 13 हजार रुपये मिलते हैं! अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कारखाना मालिकों और मजदूरों के बीच संवाद कायम करने के लिए एक समिति बनाई है। मगर साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश का शक भी जता दिया है। ऐसे में यह नहीं लगता कि मजदूर सरकार से किसी हमदर्दी की आशा कर सकते हैं। मगर ऐसे नजरियों से उस वक्त औद्योगिक शांति कायम करना कठिन होगा, जब श्रमिक वर्ग पर बढ़ते आर्थिक संकट की गहरी मार पड़ी है।

विधानसभा चुनावों के नतीजों को देखने के कई नजरिए

उमेश

बीते अप्रैल में हुए पांच राज्यों के चुनाव नतीजों को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। लेकिन देश के पूर्वी छोर पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक स्थित चार राज्यों के नतीजों को देखें तो उनमें एक बात समान नजर आती है। सभी राज्यों ने अपने यहां के उन आक्रामक नेतृत्व पर भरोसा जताया है, जिनसे विकास और नवाचार की उम्मीद है। असम में हिमंत, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और तमिलनाडु में विजयन की जीत लोकांक्षाओं के जमीनी हकीकत बनने का भरोसा है। इन राज्यों की जीत में दिखता है कि केंद्र से बिना वजह की लड़ाई का भी कोई मोल नहीं है। आज की जनता विकास चाहती है, महिलाएं सुरक्षा चाहती हैं और युवा अपने भविष्य और सपनों की गारंटी चाहते हैं। इस बार चुनाव तो पांच राज्यों में हुए, लेकिन सबसे ज्यादा में चर्चा पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा। उन्तीस अप्रैल को आखिरी दौर के मतदान के बाद आए एक्जिट पोल के नतीजों को लेकर काफी सवाल भी उठे, खासकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार की आशंका को लेकर एक्जिट पोल निशाने पर भी रहे। सिर्फ एक एक्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया ने तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजयन की पार्टी टीवीके के जीत की संभावना जताई थी। जबकि किसी भी एक्जिट पोल को तमिलनाडु में टीवीके की जीत की उम्मीद नहीं थी। सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी को क्यों हार मिली? इसमें दो राय नहीं कि 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल था। फिर भी बौद्धिकों के एक वर्ग को लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनावों के वोट के अंतर को पाटकर जीत दर्ज कर लेगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 38 प्रतिशत वोट और 77 सीटें मिली थीं। 2016 के विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को 10 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन उसे सिर्फ तीन सीटें ही मिली थीं। उसकी तुलना में देखें तो बीजेपी के लिए 2021 के चुनावी नतीजे बड़ी छलांग थे। इस ट्रेंड के हिसाब से इस बार बीजेपी की जीत सुनिश्चित लग रही थी, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन से छह सीटें कम पर संतोष करना पड़ा था। इसलिए बीजेपी की जीत को लेकर संशय भी था। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में जीत हासिल करने के लिए चुनावी रणनीति बनाई, खुद कई रोड शो किए, झारग्राम जिले में सड़क पर उतर कर बंगाल की प्रसिद्ध झालमुढ़ी का स्वाद चखा, उसने भाजपा की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। रही–सही कसर ममता बनर्जी की कुछ गलतियों ने कर दिए। बीते साल अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या पर ममता ने जिस तरह की चलताऊ राजनीति की, उससे पश्चिम बंगाल गुस्से में था। इसका असर भी दिखा और महिलाओं ने उनकी लक्ष्मी भंडार योजना में मिल रही डेढ़ हजार रूपए की रकम पर भरोसा नहीं किया और ममता को हार का सामना करना पड़ा। ममता ने भाजपा से लोगों को डराते हुए कहा कि अगर राज्य में उसकी सरकार आ गई तो वह माछ–भात खाने पर रोक लगा देगी। ममता की खासियत उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली रही है। लेकिन इस बार उनकी वह आक्रामकता ठोस मुद्दों की बजाय हल्की बातों में ज्यादा नजर आई। इसलिए उनके खिलाफ भाजपा का भय बनाम भरोसा का नारा चल गया। भारतीय जनता पार्टी की जीत में उसके रणनीतिकार अमित शाह की बड़ी भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान में घुसपैठ को मुद्दा बनाए रखा। ममता बनर्जी घुसपैठ को चलताऊ और हिंदू–मुस्लिम के बीच खाई बढ़ाने की राजनीति के मुद्दे के तौर पर लेती रहीं। भारतीय जनता पार्टी अब संतोष कर सकती है कि उसके पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रस्दा मुखर्जी के घर में भी उसका शासन है। असम के लिए घुसपैठ का मुद्दा पुराना है। हिमंत विस्वसरमा ने इस मुद्दे को खूब हवा दी। उन्होंने बार–बार कहा कि वे सत्ता में लौटे तो किसी भी घुसपैठिए को असम में नहीं रहने देंगे। असम की जनसांख्यिकी को घुसपैठ ने बहुत प्रभावित किया है। इससे असम के लोग बहुत प्रभावित हैं। अतीत में कांग्रेस की सरकारों ने इसकी तरफ या तो आंख मूंदे रखा या फिर घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। इससे असम का बहुसंख्यक वर्ग नाराज हुआ। वैसे हिमंत भी पुराने कांग्रेसी हैं। उन्हें कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरियां भी पता हैं। फिर अपने पांच साल के कार्यकाल में उन्होंने विकास को गति भी दी है। इसकी वजह से असम के लोगों ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। तीसरे बड़े राज्य तमिलनाडु में पिछले यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने भले ही गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन पच्चीस साल बाद वह अकेले दम पर 133 सीटों के साथ बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन पूरे पांच साल

के शासन काल में स्टालिन की सरकार की उपलब्धि खोजेंगे तो पाएंगे कि वह पूरे कार्यकाल में सनातन पर हमले करती रही। उसके निशाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार रही। हिंदी को मुद्दे पर भी वह तमिलनाडु के लोगों की गोलबंदी करती रही। उसने नई शिक्षा नीति को तमिल अस्मिता के लिए खतरा बताया। प्रस्तावित लोकसभा सीटों के परिसीमन को भी मुद्दा बनाया। उसके बरक्स अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजयन की पार्टी टीवीके ने लोगों के बीच पैठ बनाई। लोगों की भलाई के लिए काम किए। ठीक है कि विजयन का क्रेज युवाओं में ज्यादा है। लेकिन लोकभलाई के लिए किए गए कार्यों की वजह से वे तमिलनाडु के वरिष्ठ नागरिकों के भी चहेते बने। यही वजह है कि उनका दल राज्य में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। सत्ताधारी डीएमके दूसरे स्थान पर पिछड़ गया है। 1977 से तमिलनाडु की राजनीति दो राजनीतिक दलों डीएमके और एआईडीएमके के इर्द–गिर्द सिमट कर रह गई विजयन ने इस परिपाटी को तोड़ दिया है। तमिलनाडु में अभिनेताओं का क्रेज नई बात नहीं है। इसके पहले तमिल फिल्मों के सुपर स्टार एमजी रामचंद्रन की नवेली पार्टी एआईडीएमके को 1977 में बड़ी जीत मिली थी। देखना होगा कि वे किसका साथ लेकर नई सरकार बनाते हैं। देश ही नहीं, दुनिया की सबसे पहली चुनी हुई वामपंथी सरकार देने वाले केरल राज्य में वामपंथी मोर्चा इस बार चुनाव हार गया है। दस साल बाद उसे करारी हार मिली है। इसके साथ ही राज्य में कांग्रेस की अगुआई वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी यूडीएफ की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या देश की राजनीत तय करेंगे

अजय दीक्षित

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो भी परिणाम आएंगे वे देश के 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा ब दशा तय करेंगे। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम चार मई को आयेंगे। इन चुनावों में मुख्य मुकाबला ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तुड़मूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच है हालांकि लेफ्ट और कांग्रेस भी मैदान में है। ममता बनर्जी की तुड़मूल कांग्रेस 2011से सत्ता में है जबकि भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी वोट लाकर 294 सदस्यीय विधानसभा में 77 सीट जीती थी। लेकिन ममता बनर्जी की तुड़मूल कांग्रेस ने 48 फीसदी वोट ले कर 213 सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का सपना रहा है कि वह अंग,बंग, और कलिंग में सरकार बनाए। उसके अंग (बिहार) कलिंग (ओडिशा) में सरकार बन गई है और अब बंग (बंगाल) की बारी है। जनसंघ यानि आज की भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ही थे। स्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई कहते थे कि बंगाल जितने का सपना एक दिन पूरा होगा । लालकृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, दीन दयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेई , कृष्णलाल शर्मा ने एक सेमिनार में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि पश्चिमी बंगाल में सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि वह पैन इंडिया पार्टी बने जिसका समूचे देश में सत्ता हो । ऐसा लगता है कि भाजपा ने,80 फीसदी लक्ष पूरा कर लिया है।आज उसकी संपूर्ण हिंदी भाषा के राज्यों , पूर्वोत्तर राज्यों, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा,में सरकार है।जबकि दक्षिण भारत में कर्नाटक में सरकार रह चुकी है।केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राज्य शेष है। तेलंगाना में विरोधी दल है। अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुमत लाती है तो वह 2029 के लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर आसानी बहुमत प्राप्त कर लेगी । क्योंकि अभी 240 जीत गई थी क्योंकि महाराष्ट्र,उत्तर, प्रदेश,बंगाल लगभग 100 सीट बढ़ा लेगी जो अकड़ा 340 सीट का होगा इसमें जेडीयू,शिवसेना, एनसीपी,का योग अलग होगा ।, उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरा सवाल यह है कि अगर तुड़मूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतती है तो ममता बनर्जी राष्ट्रीय क्षितिज पर भारतीय राजनीत में 2029 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एक जुट कर अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश कर सकती है।इस घटना क्रम के बाद समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों, बीजेडी, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस,आप, ममता बनर्जी को नेता घोषित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश कर सकती है।यद्यपि कांग्रेस भी चाहेगी ये सभी पार्टियों उनके झंडे तले चुनाव लड़े और चुनाव तक ममता बनर्जी को भी इस इंडी गठबंधन में लिया जाय लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री पद से कम पर तैयार नहीं होगी। पाश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को कई मुद्दों पर घेरा है।यहां तक कि राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गुंडों की संज्ञा दी जो जनता से अवैध उगाही,कट मनी मांगते हैं। ममता बनर्जी पर उन्होंने मुस्लिम ध्रुवीकरण का आरोप भी लगाया। विपक्ष की एकता का रास्ता उत्तर प्रदेश, बिहार,से निकलेगा क्योंकि सपा नेता अखिलेश यादव, राजेडी के तेजस्वी यादव बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर उत्सुक हैं और ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं। बीजेडी के नेता नवीन पटनायक, दक्षिण में एम के स्टालिन,भी ममता बनर्जी के साथ है। इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में सपा, कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव मैदान में आ सकते हैं। दूसरी ओर बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश की तैयारी भी शुरू करदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से बिगुल फूंकना चाहते हैं और हरदोई में594 किलो मीटर सिक्स लेन गंगा एक्सप्रेस वे का लोकार्पण भी दो दिन पहले किया है। कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव मोड में आ गई है। मप्र, राजस्थान, दिल्ली,के कार्यकर्ताओं को समानांतर जिम्मेदारी दी जाएगी। राष्ट्रीय महासचिव बाल संतोष लखनऊ में है। लेकिन सपा भी तैयार है क्योंकि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होना है। देश में उत्तर प्रदेश में 80, जम्मू कश्मीर 06, हिमाचल प्रदेश 04, गोवा 02, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल कुल 10 सीट है।कुलमिलाकर 542 ।पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है जो देश की आगामी राजनीति की दिशा ब दशा तय करेंगे।

पश्चिम बंगाल में भाजपा की चली सुनामी के सियासी मायने दूरगामी महत्व वाले

कमलेश

केंद्र में विगत बारह वर्षों से सत्तारूढ़ श्भारतीय जनता पार्टीश ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में निर्णायक जीत दर्ज करके जनसंघ के संस्थापक और बंगाल मूल के दूरदर्शी हिंदूवादी राजनेता पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अद्भुत श्रद्धांजलि दी है। सच कहूं तो आरएसएस के इस सुप्रसिद्ध सिपाही का कश्मीर में दिया हुआ सियासी बलिदान व्यर्थ नहीं गया। खासकर यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भाजपा द्वारा उसे दिया हुआ बहुमूल्य वैचारिक तोहफा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में "पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन" का प्रतीक मानी जाएगी। इससे विपक्ष का शक्ति–संतुलन बदलेगा, भाजपा का राष्ट्रीय आत्मविश्वास बढ़ेगा और बंगाल की दशकों पुरानी राजनीतिक संस्कृति में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल सकता है। कम शब्दों में कहा जाए तो भय हारा और भरोसा जीता है। भद्रलोक के हृदय परिवर्तन से सोनार बंगला के बहुमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने से हिंदुओं का मनोबल बढ़ेगा और बंगलादेशी घुसपैठियों से देश को मुक्ति मिलेगी। इस शुभ घड़ी को दिखलाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, भाजपा के राष्ट्रीय अध्ययन नितिन नवीन की सूझबूझ और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सियासी तेवरों का भी अहम योगदान है। वहीं, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेताओं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सरमा के योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं, पश्चिम बंगाल के राजनेता सुवेन्दु अधिकारी, दिलीप बोस जैसे कर्मठ नेताओं और भाजपा के श्बलिदानीश कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष का प्रतिफल है। देखा जाए तो यह भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं और उनका हौसलाअफजाई करते रहने वाले स्थानीय और बाहरी नेताओं के संयुक्त प्रयासों का सकारात्मक नतीजा है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। बंगलादेश की हिन्दू विरोधी मानसिकता और ग्रेटर बंगलादेश की थ्योरी ने पूर्वी भारत के हिंदुओं को इस कदर भयभीत कर दिया है कि अब उनके पास भाजपा के नेतृत्व में गोलबंद होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा, पहले कलिंग यानी उड़ीसा, फिर अंग यानी बिहार और अब बंग यानी पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और भगवा की बुलंदी बहुत कुछ राजनीतिक चुगली करती है, जिसे समझने, और जनमानस को समझाने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में बसे पूर्वी भारत के कर्तव्यनिष्ठ आरएसएसध्भाजपा नेताओं–कार्यकर्ताओं की मानें तो यह उनके सामूहिक प्रयासों की विजय हैजो अनवरत रूप से जारी अथक जनसंघर्षों और कार्यकर्ताओं के बलिदानों की वजह से मिली है। लिहाजा इसके राजनीतिक निहितार्थ केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति, संघीय ढांचे और विपक्ष की रणनीति पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं, निकट भविष्य में पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया तक में इसकी अनुगूंज सुनाई पड़ेगी। पश्चिम बंगाल लंबे समय तक वामपंथ और बाद में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहां भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि पार्टी अब हिंदी पट्टी से आगे निकलकर पूर्वी भारत में स्थायी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। इससे ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर में भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। अन्य राज्यों में विस्तार भी होगा। ममता बनर्जी विपक्षी राजनीति की सबसे आक्रामक नेताओं में मानी जाती रही हैं। बंगाल में हार होने पर उनकी "राष्ट्रीय विकल्प" वाली छवि को गहरा झटका लगेगा। इंडिया गठबंधन की राजनीति में उनका प्रभाव कम हो सकता है और विपक्ष का नेतृत्व पुनः बिखर सकता है। जबकि राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनकी टांग खींचने वाले सारे क्षेत्रीय नेता उनकी सटीक रणनीति से सियासी धूल फांकने को अभिशप्त हुए। इससे भविष्य में कांग्रेस लाभान्वित होगी। पश्चिम बंगाल में पहले ही चुनाव भाजपा बनाम तृणमूल तक सिमटता दिख रहा है। भाजपा की जीत होने पर यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस और वामदलों की पारंपरिक राजनीति बंगाल में अप्रासंगिक हो चुकी है। भाजपा ने बंगाल में राष्ट्रवाद, सीमा सुरक्षा, घुसपैठ, नागरिकता और हिंदू पहचान के मुद्दों को कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़कर चुनावी रणनीति बनाई है। यदि यह सफल होती है, तो पार्टी इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी और आक्रामक रूप से लागू करेगी। बंगाल लंबे समय तक वैचारिक राजनीति, वामपंथी विमर्श और क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। भाजपा की जीत यह संकेत देगी कि बंगाल की राजनीति अब वैचारिक संघर्ष से निकलकर राष्ट्रीय ध्रुवीकरण और पहचान–आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है। भाजपा द्वारा बंगाल जीत से 2029 लोकसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी। बंगाल की 42 लोकसभा सीटें राष्ट्रीय सत्ता संतुलन में बेहद महत्वपूर्ण हैं। भाजपा यह संदेश दे सकेगी कि उसका विस्तार अब दक्षिण और पूर्व भारत तक स्थायी रूप से हो चुका है। पश्चिम बंगाल में भाजपा का संगठन वर्षों तक कमजोर माना जाता था। यदि पार्टी सत्ता तक पहुंचती है, तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के दीर्घकालिक कैडर विस्तार मॉडल की बड़ी सफलता मानी जाएगी। सोशल और वैचारिक स्तर पर संघ की पैठ को भी मजबूती मिलेगी। अब तक बंगाल और केंद्र सरकार के संबंध अक्सर टकरावपूर्ण रहे हैं। भाजपा सरकार बनने पर केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बढ़ेगा, जिससे निवेश, बुनियादी ढांचे और केंद्रीय परियोजनाओं को गति मिल सकती है। हालांकि विपक्ष इसे "संघीय ढांचे के केंद्रीकरण" के रूप में भी प्रस्तुत कर सकता है। सीमा पार घुसपैठ, एनआरसी–सीएए, बांग्लादेश सीमा और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मुद्दे बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे। भाजपा की जीत इन मुद्दों को राष्ट्रीय बहस में और प्रमुख बना सकती है। यह कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत केवल सरकार बदलने की घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारतीय राजनीति में "पूर्वी भारत के वैचारिक परिवर्तन" का प्रतीक मानी जाएगी।

खाद्य सुरक्षा से खाद्यान्नों के मामले में नेतृत्व की ओर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पीएलआई योजना का परिवर्तनकारी प्रभाव

अविनाश

खाद्यान्नों से जुड़ी भारत की कहानी में एक निर्णायक मोड़ भारत आज अपने आर्थिक सफर के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अब जबकि हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में अग्रसर है, विकास को सिर्फ उत्पादन की मात्रा से ही नहीं, बल्कि हमारे द्वारा सृजित मूल्य के आधार पर भी मापना होगा। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की तुलना में बहुत कम क्षेत्र ही ऐसे हैं, जहां इस प्रकार का बदलाव बिल्कुल साफ नजर आता है। भारत खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, दूध और समुद्री उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। दशकों तक, हमारे कृषि संबंधी सामर्थ्य ने देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। फिर भी, इस उपज का एक बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से बेहद ही सीमित मूल्यवर्धन के साथ सीधे खेत से बाजार तक पहुंचता रहा। आज भारत के कृषि उत्पादन का महज 12–13 प्रतिशत हिस्सा ही प्रसंस्करण से गुजरता है। उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच का यही अंतर भारतीय अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सबसे बड़े अवसरों में से एक है। इसलिए, खाद्यान्नों से जुड़ी भारत की यात्रा का अगला चरण बिल्कुल स्पष्ट हैरू कृषि की प्रचुर संपदा को उच्च मूल्य वाले एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी खाद्य उत्पादों में परिवर्तित करना। पीएलआई योजना के पीछे की परिकल्पना

इस अवसर को पहचानते हुए, भारत सरकार ने मार्च 2021 में कुल 10,900 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) की शुरुआत की। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा इस योजना को 2021–22 से 2026–27 तक की छह साल की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। इस योजना के पीछे का मूल विचार सरल लेकिन ठोस हैरू खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, नवाचार और वैश्विक ब्रांडिंग के विस्तार में निवेश करने वाली कंपनियों को पुरस्कृत करना। कुल मिलाकर, यह योजना इन–स्टोर ब्रांडिंग, अंतरराष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं में शेल्फ स्पेस और वैश्विक विपणन अभियानों में निवेश करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करके भारत में खाद्य उत्पादन से जुड़ी वैश्विक स्तर की कई चौंपियन कंपनियां तैयार करती है। रणनीतिक डिजाइन एक आधुनिक खाद्य इकोसिस्टम का निर्माण पीएलआईएसएफपीआई योजना की संरचना को सावधानीपूर्वक को तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित रखा गया है। 1. उच्च क्षमता वाले खाद्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना पहला घटक पकाने के लिए तैयार (रेडी–टू–कुक) और खाने के लिए तैयार (रेडी–टू–ईट) खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद जैसी प्रमुख खाद्य श्रेणियों में उत्पादन बढ़ाने पर केन्द्रित है। ये श्रेणियां वैसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत घरेलू खपत और निर्यात क्षमता, दोनों में तेजी से विस्तार कर सकता है।

1. नवाचार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी को प्रोत्साहन देना दूसरा घटक एमएसएमई द्वारा विकसित नवोन्मेषी और जैविक खाद्य उत्पादों को समर्थन प्रदान करता है। लघु एवं मध्यम उद्यम भारत के खाद्य क्षेत्र की रीढ़ हैं और समावेशी विकास हेतु आधुनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ उनका जुड़ाव बेहद जरूरी है। वर्ष 2023 में, अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट्स) वर्ष के उपलक्ष्य में, मंत्रालय ने पीएलआई योजना के तहत एक विशेष पहल की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य पकाने के लिए तैयार (रेडी–टू–कुक) और खाने के लिए तैयार (रेडी–टू–ईट) उत्पादों में मिलेट्स के उपयोग को प्रोत्साहित करना था। मिलेट्स जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी, अत्यधिक पौष्टिक और भारत की कृषि परंपराओं में गहराई से जुड़े हुए हैं। आधुनिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मिलेट्स का समावेश करके, यह योजना पोषण संबंधी सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी कृषि को एक साथ बढ़ावा देती है। बदलाव से जुड़े आंकड़े पीएलआई योजना के तहत बहुत ही कम समय में हासिल की गई प्रगति उद्योग जगत की ओर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और इस नीति की प्रभावशीलता को दर्शाती है। अब तक इस योजना के तहत 165 कंपनियों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 68 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) हैं, साथ ही बड़ी कंपनियों के 40 संविदा निर्माता भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 9,207 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है। प्रति वर्ष लगभग 35 लाख मीट्रिक टन की नई प्रसंस्करण और संरक्षण संबंधी क्षमता सृजित की गई है। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3.29 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस योजना का मूल लक्ष्य 25 लाख रोजगार सृजित करना था। इस क्षेत्र ने पहले ही इस लक्ष्य का 131 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर लिया है। पीएलआई समर्थित कंपनियों द्वारा प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री में भी 2019–20 से 13.23 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादन पर आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के 14 क्षेत्रों को कवर करती है। इनमें से, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित पीएलआई सबसे प्रभावशाली योजनाओं में से एक बनकर उभरी है। कुल पीएलआई सब्सिडी वितरण में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का हिस्सा मात्र 8 से 9 प्रतिशत ही होने के बावजूद, इसने तमाम पीएलआई योजनाओं के तहत सृजित किए गए कुल रोजगारों में से लगभग 42 प्रतिशत रोजगार सृजित किए हैं। अब तक, इस योजना के तहत कुल 2715 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की जा चुकी है। यह कुल परिव्यय का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा है। यह साबित करता है कि खाद्य प्रसंस्करण भारत के मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम में सबसे अधिक रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों में से एक है। बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में काम करने वाले पेशेवर अक्सर पकाने के लिए तैयार (रेडी–टू–कुक) या खाने के लिए तैयार (रेडी–टू–ईट) वैसे गुणवत्तापूर्ण भोजन की तलाश में रहते हैं जो उनकी तेज रफ्तार जीवनशैली के अनुरूप हो।

खाद्य सुरक्षा से खाद्य नेतृत्व की ओर भारत की प्रचुर कृषि संपदा इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे सामने इस प्रचुर संपदा को सतत आर्थिक मूल्य में बदलने की चुनौती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना इस बदलाव को गति देने में सहायक साबित हो रही है और खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर खाद्यानों के मामले में नेतृत्व का सपना शीघ्र ही साकार होने वाला है।

पुलिस मुठभेड़, एक बदमाश घायल गिरफ्तार फायरिंग के बाद धराया आरोपी, तमंचा–कारतूस बरामद एक फरार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जलालपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार होने में सफल रहा। इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी केराकत अजीत कुमार सिंह ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष के निर्देशन में थानाध्यक्ष जलालपुर के नेतृत्व में टीम डिंगुरपुर नहर रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भाऊपुर की ओर से बाइक सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देने पर दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे एक बदमाश घायल हो गया। भागने के प्रयास में बाइक सवार संतुलन खो बैठे और पीछे बैठा बदमाश गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया, जबकि चालक फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अंकित यादव निवासी बहाउद्दीनपुर थाना सरायख्वाजा के रूप में हुई है। उसके पास से .315 बोर का तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फरार आरोपी की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। इस मामले में थाना जलालपुर मे धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।

पुलिस मुठभेड़, शातिर बदमाश गिरफ्तार हत्या के प्रयास समेत कई मुकदमों में वांछित, तमंचा व बाइक बरामद साथी फरार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में बुधवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस मामले में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी शाहगंज गिरेन्द्र सिंह ने बताया कि सरायख्वाजा थाना की टीम मल्हनी–कोइरिडीहा मार्ग पर नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कोइरिडीहा की

ओर से बाइक सवार दो संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर दोनों नहर पटरी की ओर भागने लगे। पीछा करने पर कुछ दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। बदमाशों ने पुलिया की आड़ लेकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के बाद पुलिस ने तलाशी ली तो एक बदमाश घायल अवस्था में मिला, जबकि दूसरा फरार हो गया। घायल आरोपी की पहचान कृष्णा यादव, पुत्र संजय यादव, निवासी छबिलेपुर थाना सरायख्वाजा के रूप में हुई है। उसके पास से .315 बोर का तमंचा बरामद हुआ, जिसमें एक खोखा कारतूस फंसा था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने साथी विकास के साथ मिलकर लूट, छिनैती और सुपारी लेकर अपराध करता है। पुलिस ने घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है और फरार आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। इस संबंध में बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों संग की बैठक

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। 9 मई 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला जज/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर, श्री सुशील कुमार शशि ने आज (6 मई 2026) समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की। यह जानकारी सिविल जज सी.डी./सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर, सुशील कुमार सिंह ने दी है। बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार लोक अदालत में सुलह–समझौते योग्य मामलों के निस्तारण की समीक्षा करना था। जिला जज ने न्यायिक अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों और मजिस्ट्रेटों को सुलह–समझौते के आधार पर मामलों के निस्तारण में आ रही किसी भी कठिनाई को दूर करने का निर्देश दिया। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों के निस्तारण की संख्या को बढ़ाना है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री–लिटिगेशन (वाद–पूर्व) स्तर पर कई प्रकार के मामले निपटाए जाएंगे। इनमें पारिवारिक/दाम्पत्य विवाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जल बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), भरण–पोषण वाद तथा अन्य प्रकार के आपराधिक शमनीय व सिविल वाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, न्यायालयों में लंबित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम एवं सेवायोजन विवाद, विद्युत, जलकर बिल एवं अन्य प्रकार के बिलों के भुगतानों के विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), वैवाहिक प्री–लिटिगेशन के मामले, पारिवारिक वाद (विवाह विच्छेद संबंधित वादों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा में वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों से संबंधित विवाद, राजस्व वाद और अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) भी आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। जिला जज ने वादकारियों और अधिवक्तागण से अपील की है कि वे अपने–अपने वादों से संबंधित न्यायालयों में संपर्क स्थापित कर मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु संदर्भित कराएं। उन्होंने अधिकतम वादों का निस्तारण कराकर लोक अदालत का लाभ उठाने का आग्रह किया।

प्रवेश में पिछले चार साल का रिकॉर्ड टूटा, निजी स्कूलों में हुए 1.43 लाख से अधिक प्रवेश

लखनऊ, (संवाददाता)। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत इस वर्ष प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया ने पिछले चार वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग की सख्ती और नियमित समीक्षा के चलते सत्र 2026–27 में अब तक 1.43 लाख से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश कराया जा चुका है। कुल 1.95 लाख आवंटित सीटों के सापेक्ष यह संख्या उल्लेखनीय है और पिछले वर्ष के 1.40 लाख प्रवेश से अधिक है। इस बार आवेदन प्रक्रिया को तीन चरणों में सीमित रखा गया और अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर प्रगति की निगरानी की गई। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जिलास्तरीय अधिकारियों को हर आवंटित बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

डीएम सैमुअल पॉल एन. का कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कार्यालय का किया निरीक्षण, गंदगी पर नाराजगी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में नवागत जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों और पटलों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखों के रख–रखाव, कार्यालयी कार्यप्रणाली, लंबित प्रकरणों तथा जनहित से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की। कई कार्यालयों में गंदगी पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को तत्काल साफ–सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने नजारत कक्ष का निरीक्षण करते हुए एआरके बाबू से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान समयबद्ध तरीके से किया जाए, जिससे कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी न हो। इसके साथ ही एलआरसी से वेतन भुगतान की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए किसी भी प्रकार की देरी न करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में डीएम ने आईजीआरएस कक्ष, अभिलेखागार (रिकॉर्ड रूम), अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) न्यायालय, भूमि राजस्व अनुभाग, उप जिलाधिकारी न्यायालय सदर, नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लीगल एड क्लिनिक, तहसील विधिक सेवा समिति, रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय, भूलेख अनुभाग, आपदा प्रबंधन कार्यालय, अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, नायब तहसीलदार न्यायालय, उप जिलाधिकारी सदर कार्यालय तथा जनगणना कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आईजीआरएस से संबंधित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने और शिकायतकर्ताओं से अनिवार्य रूप से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जन शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता और तत्परता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपर जिलाधिकारी को कलेक्ट्रेट परिसर में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुचारू बनाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा, अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व) अजय अम्बष्ट, नगर मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन, उपजिलाधिकारी सदर संतवीर सिंह तथा जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जौनपुर में जनगणना 2027 की स्व-गणना 7 मई से, 21 मई तक चलेगा अभियान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में जनगणना 2027 के तहत स्व–गणना (सेल्फ–एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया जनपद में 7 मई से शुरू होकर 21 मई तक संचालित की जाएगी। इस संबंध में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें स्व–गणना की प्रक्रिया और उसकी महत्ता पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण के तहत सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारी और आमजन को निर्धारित अवधि में स्वयं ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर जाकर 33 बिंदुओं से संबंधित सूचनाएं भरनी होंगी। उन्होंने कहा कि एक बार डिजिटल माध्यम से जानकारी दर्ज हो जाने के बाद बार–बार विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के लिए स्व–गणना अभियान को सफल बनाने हेतु अलग–अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग ले सकें। जिलाधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस अभियान का व्यापक प्रचार–प्रसार करें और लोगों को स्व–गणना के प्रति जागरूक बनाएं। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जनपद में शत–प्रतिशत भागीदारी हो, क्योंकि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है। जिला जनगणना अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) परमानंद झा ने बताया कि संबंधित पोर्टल का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रश्नों का उत्तर सावधानीपूर्वक और सटीकता के साथ भरा जाए तथा अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी विवरणों की जांच अवश्य कर ली जाए। सबमिट करने के बाद प्राप्त एसई–आईडी को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है। प्रेस वार्ता में जनगणना निदेशालय के प्रतिनिधि युवराज गर्ग ने स्व–गणना की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए पोर्टल पर पंजीकरण, सत्यापन और डेटा प्रविष्टि के विभिन्न चरणों को समझाया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (भू–राजस्व) अजय अम्बष्ट, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय सहित अन्य अधिकारी एवं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

मेदांता अस्पताल में अजय राय से मिले प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की दुआ

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के मेदांता अस्पताल में सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय से प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुलाकात कर उनका कुशल–क्षेम जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की दुआ की। इस दौरान मुलाकात का माहौल सौहार्दपूर्ण रहा और गंगा–जमुनी तहजीब की झलक देखने को मिली।मुलाकात करने वालों में शाही इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष और प्रमुख शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी तथा ऑल इंडिया

शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास शामिल रहे। सभी ने अजय राय के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री मुईद अहमद, निवर्तमान प्रदेश महासचिव मुकेश सिंह चौहान और अरशद आजमी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।मुलाकात के दौरान अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रेम, भाईचारे और समावेशी राजनीति की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सम्मानित स्तंभों का समर्थन पार्टी के संघर्ष को नई ऊर्जा देता है और प्रबुद्धजनों का यह अपनत्व कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती प्रदान करता है।अजय राय ने आगे कहा कि यह मुलाकात गंगा–जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे की उस अटूट परंपरा का प्रतीक है, जिसे सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध रही है।

स्कूलों के पास ट्रैफिक जाम पर हाईकोर्ट सख्त

लखनऊ, (संवाददाता)। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राजधानी के स्कूलों के पास ट्रैफिक जाम होने पर नाराजगी व्यक्त कर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पहले के आदेशों का पालन न होने पर संबंधित अफसरों समेत स्कूलों को कड़ी फटकार लगाई है । कोर्ट ने कहा कि इस समस्या के समाधान को न तो सरकारी अधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं और न ही स्कूलों के प्रबंधन ने इसमें रुचि दिखाई है। यह भी टिप्पणी की कि पिछले आदेश के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस मुद्दे पर हुई पिछली बैठक को अधिकारियों और स्कूलों दोनों ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने यह भी बताया कि कई सक्षम अधिकारी बैठक में अनुपस्थित थे, जबकि स्कूलों की ओर से ऐसे प्रतिनिधि आए थे जो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थे। इस पर न्यायालय ने असंतोष व्यक्त किया। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों को उनके आसपास के यातायात प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाने हेतु कुछ दिशानिर्देश तैयार करने के राज्य के प्रस्ताव को सरकार के विभिन्न विभागों के साथ–साथ लखनऊ के विभिन्न स्कूलों में भी प्रसारित करे। जिससे कि सभी स्कूलों के लिए प्रस्तावित दिशानिर्देशों को वे पढ़कर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देते समय उनपर विचार करके अनुमोदित किया जा सकेगा। सुनवाई के दौरान न्यायालय के संज्ञान में आया ।

मेदांता लखनऊ ने शुरू की निःशुल्क ओपीडी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आशियाना स्थित सेकंड इनिंग्स सीनियर सिटीजन्स क्लब में निरूशुल्क ओपीडी सेवा की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य बुजुर्गों को उनके नजदीक ही अनुभवी डॉक्टरों से परामर्श उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अस्पताल जाने की परेशानी से राहत मिल सके। इस ओपीडी में वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. महिम मित्तल, डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह देंगे। डॉ. मित्तल को चिकित्सा क्षेत्र में 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और वे लंबे समय से जटिल बीमारियों के इलाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह ओपीडी प्रत्येक माह के पहले बुधवार को सुबह 09:00 बजे से 11:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस पहल के बारे में डॉ. महिम मित्तल ने कहा, "हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों को समय पर सही सलाह और देखभाल मिल सके। उम्र बढ़ने के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आती हैं, जिनका इलाज नियमित जांच और मार्गदर्शन से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस तरह की ओपीडी से मरीजों को नजदीक ही विशेषज्ञ सेवाएं मिलेंगी और उनकी परेशानी कम होगी।" सेकेंड इनिंग्स सीनियर सिटिजन क्लब के फाउंडर अतुल दुबे ने बताया कि इस तरह की सेवाएं बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी हैं क्योंकि उन्हें अक्सर अस्पताल तक पहुंचने में दिक्कत होती है। यह पहल न सिर्फ उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएगी बल्कि मुश्किल समय में लोगों की जान बचाने में भी मददगार साबित होगी। हम क्लब के सदस्यों की ओर से मेदांता को धन्यवाद देते हैं। यह निरूशुल्क ओपीडी 1289, सेक्टर ज्ञ, आशियाना, लखनऊ में आयोजित की जा रही है, जहां वरिष्ठ नागरिक आसानी से पहुंचकर अपने स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह ले सकते हैं।

बरसठी में बाबा साहेब की प्रतिमा पर कीचड़ फेंका, ग्रामीणों में आक्रोश

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित बरसठी थाना क्षेत्र के गहली गांव में मंगलवार देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कीचड़ फेंकने का मामला सामने आया है। घटना से गांव में आक्रोश फैल गया बुधवार सुबह प्रतिमा की स्थिति देखकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि यह घटना सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि दोषियों की पहचान कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। साथ ही क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करने तथा सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात कही गई, जिस पर ग्रामीणों ने सहमति जताई। ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही, हालांकि प्रशासन की सक्रियता से हालात फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं।वही इस मामले में जानकारी लेने पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पहुंची है ग्रामीणों को समझबुझाकर मामले को शांत कराया गया है।जो भी लोग दोषी होगे उनको चिन्हित करके कार्यवाही किया जाएगा।बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने को आदेश दिया है।मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

अब दस वर्ष की किस्त पर मिलेंगे फ्लैट, नौ के बजाय सात प्रतिशत सलाना की दर से लिया जाएगा ब्याज

लखनऊ, (संवाददाता)। देवपुर पारा स्थित एलडीए की अटल नगर बहुमंजिला आवासीय योजना में फ्लैट लेने वालों को अब सात के बजाय दस वर्ष की मासिक किस्तों में पैसा अदा करने की सहूलियत मिलेगी। किस्तों पर ब्याज भी नौ की जगह सात प्रतिशत सालाना की दर से लिया जाएगा। एलडीए वीसी ने इसका आदेश जारी कर दिया। वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना में 12 से लेकर 19 मंजिल के 15 टावरों में 2496 फ्लैट हैं। 30 से लेकर 54.95 वर्गमीटर के इन फ्लैटों की कीमत 9.83 लाख रुपये से शुरू होती है। टू बीएचके फ्लैट 16 से 21 लाख रुपये के बीच हैं। यहां ज्यादातर फ्लैटों का लॉटरी से आवंटन हो चुका है। इस समय

630 फ्लैट खाली हैं। इनमें से 539 वन बीएचके और 91 टू बीएचके के हैं। 18 अप्रैल को खोला गया पंजीकरण 17 मई तक चलेगा। पुरानी व्यवस्था के तहत आवंटियों को सात वर्ष की 84 किस्तों में नौ प्रतिशत की वार्षिक दर पर भुगतान करना होता था। वन बीएचके के फ्लैट की मासिक किस्त करीब 15,000 रुपये बनती थी। लोगों की मांग पर समीक्षा के बाद छूट का प्रावधान किया गया है। अब सात प्रतिशत की दर से वन बीएचके फ्लैट की किस्त 10,767 रुपये बनेगी। आवंटन करा चुके लोगों को भी मिलेगा लाभ रू वीसी ने बताया कि नए आदेश का लाभ उन्हें भी मिलेगा, जिन्हें फ्लैट आवंटित हो चुके हैं। इसके लिए योजना के संपत्ति प्रभारी से मिलकर आवेदन देना होगा। फ्लैट से अधिक दावेदाररू योजना में फ्लैट का ऑनलाइन पंजीकरण एलडीए की वेबसाइट से होगा। वन बीएचके फ्लैट के लिए 55,658 रुपये और टू बीएचके फ्लैट के लिए 1,00,852 रुपये पंजीकरण शुल्क है। आवंटन न होने पर यह रकम आवेदक को लौटा दी जाएगी। बीते 15 दिनों में 2108 लोगों ने रजिस्ट्रेशन बुकलेट खरीदी है, जिनमें से 642 ने पंजीकरण करा लिया है।

20 लाख की आबादी आंधी-पानी से बिजली-पानी को तरसी

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी में सोमवार को शहर से गांव तक की 20 लाख की आबादी को आंधी–पानी ने आठ घंटे तक बिजली–पानी के लिए तरसा दिया। यह संकट 50 से ज्यादा 33 हजार, 11 हजार, 440 वोल्ट की लाइनों पर पेड़ गिरने से आया। इस दौरान 40 खंभे व तार क्षतिग्रस्त हो गए। 25 खंभे तो अमौसी जोन के हैं। विकासनगर में सबसे ज्यादा देर तक लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। विकासनगर में आम का पेड़ गिरने से कार दब गई। 11 हजार व 440 वोल्ट की लाइन के तार भी टूटे तो उपकेंद्र के आसपास का एरिया शाम तक बिजली संकट झेलता रहा। अहिबरनपुर उपकेंद्र की एसबीआई कॉलोनी के दो खंभे टूट गए तो तीन घंटे में वैकल्पिक स्रोत से बिजली तो चालू कर दी गई, मगर नए खंभे शाम तक लग सके। इसी प्रकार जानकीपुरम, तिवारीगंज, बीकेटी, इटौंजा आदि में पेड़ व टहनी गिरने से बिजली ठप हुई।

विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल हो अयोध्या - आलोक

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। अयोध्या को "भारत की धार्मिक राजधानी" एवं विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल करने की मांग आलोक सिंह राना ने उठाई है। इस संबंध आलोक सिंह राना ने मंडलायुक्त श्री राजेश कुमार जी से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा।पुनर्जागरण संस्थान के अध्यक्ष एवं "राम का घर" के प्रबंधक आलोक सिंह राना ने मंडलायुक्त अयोध्या को ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अयोध्या जिस तीव्र गति से विकसित हो रही है, उसे और आगे बढ़ाकर एक सुनियोजित दृष्टिकोण के साथ पूर्ण रूप से स्थापित किया जाना आवश्यक है। राना ने कहा कि अयोध्या की पहचान पहले से ही एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में है और वर्तमान में हो रहे विकास कार्य राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, श्रीराम जन्मभूमि पथ, आस्था पथ एवं भारत रथ इस दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी विकसित हो रहे कॉरिडोरों को केवल अवसंरचना के रूप में नहीं, बल्कि धार्मिक अनुभव के रूप में आगे बढ़ाकर एकीकृत रूप से विकसित किया जाय, जिससे सम्पूर्ण अयोध्या "लिविंग रामायण एक्सपीरियंस सिटी" के रूप में उभरे।उन्होंने सुझाव दिया है कि घाटों का पुनरोद्धार, आधुनिक अवसंरचना, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं नगर विस्तार जैसे कार्यों को एक समन्वित विरासत मॉडल से जोड़ा जाए, 'ताकि विकास और परंपरा का संतुलन बना रहे।' आलोक ने कहा कि नए विकसित पथ के एकरूप फसाड विकास को स्थायी नीति के रूप में लागू किया जाए। सभी नए निर्माण में 'आधुनिकता के साथ विरासत का संरक्षण हो' । शहर की लाइटिंग, साइनज, मूर्तिकला एवं सार्वजनिक स्थलों को रामायण थीम से जहां जुड़ रह हैं साथ ही प्राचीन धरोहरों को भी सम्मिलित किया जाए।अयोध्या को एक खुला जीवंत सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए।उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि अयोध्या को यूनेस्को की "विश्व विरासत नगर" की सूची में सम्मिलित कराने की दिशा में औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जिससे इस विकसित होती नगरी को अंतरराष्ट्रीय संरक्षण एवं पहचान प्राप्त हो सके। आलोक ने प्रशासन से अनुरोध किया।

कुलपति ने निरीक्षण के दौरा अनुरूप नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश

अयोध्या। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की एनईपी के तहत स्नातक एवं परास्नातक सम सेमेस्टर की परीक्षाएं मंगलवार से तीन पालियों में शुरू हो गई। परीक्षा के प्रथम दिन कुलपति डॉ. बिजेन्द्र सिंह ने अम्बेडकरनगर और अयोध्या के केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राम समुझ महाविद्यालय, रतनपुर (अम्बेडकरनगर) एवं कल्पना शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदरगंज अयोध्या परीक्षा केन्द्र पर अनियमितताएं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए केन्द्र को निरस्त कर दिया गया। वहीं राम समुझ महाविद्यालय, रतनपुर (अम्बेडकरनगर) केन्द्र की सभी परीक्षाएं अब कर्मयोगी रामसूरत त्रिपाठी महाविद्यालय, सकरवारी (अम्बेडकरनगर) में आयोजित होंगी तथा कल्पना शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदरगंज अयोध्या परीक्षा केन्द्र की परीक्षाएं राजा अखण्ड प्रताप महाविद्यालय, खपराडीह व रामसुचित सिंह सरस्वती महाविद्यालय, तारून अयोध्या में होंगी। कुलपति के औचक निरीक्षण एवं सचल दल की रिपोर्ट के आधार पर अन्य कई परीक्षा केन्द्रों में भी परिवर्तन किया। एसडीजेपी महाविद्यालय उल्ला निजामपुर, कौलेश्वर सूर्यमती महाविद्यालय मोहनपुर गिलन्ट (अकबरपुर) तथा कर्नल जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय, लोरपुर तजान (अकबरपुर, अम्बेडकरनगर) की परीक्षाएं अब भानमती स्मारक महाविद्यालय, अकबरपुर (अम्बेडकरनगर) केन्द्र पर आयोजित की जाएंगी। वहीं ग्रामोदय आश्रम पीजी कालेज वीरसिंह, सया अम्बेडकर नगर के छात्रों की परीक्षा रामसुचित सिंह सरस्वती महाविद्यालय, तारून अयोध्या में होगी।ये परिवर्तन 7 मई से प्रभावी होंगे।कुलपति ने निरीक्षण के दौरान सभी केन्द्राध्यक्षों को शासन की मंशा के अनुरूप नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त सचल दल ने कई अन्य केन्द्रों का भी औचक निरीक्षण किया।प्रथम पाली की परीक्षा प्रातः 8:30 से 10:30 बजे तक, द्वितीय पाली की परीक्षा 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक तथा तृतीय पाली की परीक्षा 2:30 से 4:30 बजे तक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सकुशल सम्पन्न हुई। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक विनय कुमार सिंह ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान अम्बेडकरनगर के विभिन्न केन्द्रों पर लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय के कंट्रोल रूम से सभी केन्द्रों के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जा रही है।स्नातक एवं परास्नातक सम सेमेस्टर परीक्षा में कुल 5,36,704 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए पांच जनपदों में 472 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन हेतु 19 नोडल केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। सभी केन्द्राध्यक्षों को परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मंडलायुक्त ने निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक कर दिए आवश्यक निर्देश

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।मंडलायुक्त राजेश कुमार की अध्यक्षता में अयोध्या मंडल के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक विगत देर रात आयुक्त सभागार में आयोजित की गई।बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारी एवं पांच करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों से जुड़े कांट्रेक्टर उपस्थित रहे।समीक्षा के दौरान प्रगति में चल रहे निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध पूर्णता पर विशेष जोर दिया।उन्होंने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं तय समय सीमा में पूर्ण किए जाएं, ताकि आमजन को शीघ्र लाभ मिल सके।मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने तथा कार्यस्थल पर आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। बैठक के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में आ रही बाधाओं पर चर्चा भी की गई तथा उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान किए गए।

सपा महिला नेताओं का हुआ भव्य स्वागत

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिलाध्यक्ष सरोज यादव ने बताया कि जनपद अयोध्या में महिला सभा की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर, मछलीशहर की विधायक रागिनी सोनकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी पाल तथा पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा के अयोध्या आगमन पर संगठन द्वारा उनका फूल–मालाओं एवं अंगवस्त्र भेंट कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया।इस अवसर पर महिला सभा की पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया और अपने नेताओं के प्रति उत्साह व्यक्त किया। विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, वही ऊर्जा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बनाए रखना होगा। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे समाज में जागरूकता फैलाएं, क्योंकि महिलाएं आधी आबादी हैं और किसी भी बदलाव की महत्वपूर्ण शक्ति बन सकती हैं।राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सभा सीमा राजभर ने अपने संबोधन में महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के अधिकार, सम्मान और समानता के लिए प्रतिबद्ध रही है और आगे भी यह संघर्ष जारी रहेगा।इस अवसर पर पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष राजकुमारी कोरी, यशोमति कोरी, दर्शना कोरी, पूजा वर्मा, ममता कोरी, निशात अख्तर, सुनीता कोरी, संजय चौधरी, सुनील चौधरी, पंकज कोरी, राज पासवान,सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।

भव्य पीडीए जन पंचायत चौपाल का हुआ आयोजन

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। समाजवादी पार्टी की पार्षद ज्ञानमती पासवान एवं ओपी पासवान द्वारा अपने पूज्य माता–पिता जी मूर्ति का अनावरण एवं भव्य पीडीए जन पंचायत चौपाल का आयोजन संपन्न हुआ।इस मौके पर मुख्य अतिथि सांसद अवधेश प्रसाद,रागिनी सोनकर विधायक मछलीशहर व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने किया।समाजवादी विचारधारा को जन–जन तक पहुँचाने के संकल्प के साथ समाजवादी पार्टी की पार्षद ज्ञानमती पासवान एवं ओपी पासवान द्वारा अपने पूज्य माता–पिता की मूर्ति का अनावरण एवं भव्य पीडीए जन पंचायत चौपाल का आयोजन पुरुषोत्तम नगर वार्ड में किया गया,कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव व संचालन महासचिव हामिद जाफर मीसम ने किया।कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि सांसद अवधेश प्रसाद, रागिनी सोनकर विधायक (मछलीशहर),व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन व विशिष्ट अतिथि महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा राजभर,जानकी पाल, पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा थी ,इस मौके पर मुख्य अतिथि रागिनी सोनकर ने कहा कि आज की भाजपा सरकार आधी आबादी को उसका हक नहीं देना चाहती इसलिए वो जनता को गुमराह कर रही है आज गैस के दाम आसमान छू रहे हैं प्रीपेड मीटर लगाकर जनता पर एक और बोझ लादने का काम ये सरकार कर रही है।उन्होंने कहा कि अगर अच्छी शिक्षा, महिलाओं को पेंशन व युवा रोजगार चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही ये मुमकिन है क्युकी समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया है, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने कहा कि अयोध्या के किसानों की जमीन सरकार ने जबरन लेकर अपने उद्योगपति को सौप दी।आज दलितों पर जब उत्पीड़न होता है तो बाबा के बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है शहनवा में कोरी समाज की बिटिया का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, अयोध्या में ब्राह्मण समाज की बिटिया की हत्या हुई नाका में मुस्लिम समाज की बिटिया की हत्या हुई उनके हत्यारों के घरों पर बाबा का बुलडोजर क्यू नहीं चलता, 2027 में सर्व समाज इसका जवाब श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बना कर देगा महानगर प्रवक्ता राकेश यादव एडवोकेट नहीं बताया।इस मौके पर प्रदेश सचिव राम अचल यादव, महानगर उपाध्यक्ष चंद्र यादव, लीलावती कुशवाहा, हाजी फिरोज खान गब्बर कई पदाधिकारी तथा अन्य लोग मौजूद रहे।

पहले गुड खाकर पिए पानी फिर सुनाएं अपनी समस्या, महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला की सराहनीय पहल

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। पहले गुड खाकर पिये पानी फिर सुनाये अपनी समस्या।यह नजारा महिला थाना परिसर में बुधवार को दिखाई दिया।बताते चले इस गर्मी तथा तेज धूप में महिला थाना परिसर में आने वाली सभी महिला फरियादियों को सबसे पहले महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला गुड खिलाकर पानी पिला रही है।उसके बाद उनके शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुनकर उसका निराकरण कर रही हैं।बताते चलें कि बुधवार को एक बार फिर तेज धूप व गर्मी के चलते लोग बेहाल दिखे।यही नजारा महिला थाना परिसर में दूर दराज से आने वाले फरियादियों की भी रही।वहां पर आने वाले महिला फरियादी पसीने से तरबतर और गर्मी से बेहाल दिखाई दे है।उन्होंने वहां पर आने वाले फरियादियों को गर्मी तथा धूप से राहत दिलाने के लिए गुड तथा पानी की व्यवस्था कर रखी है।वहां पर जो भी फरियादी आता है सबसे पहले गर्मी तथा धूप से राहत पाने के लिए गुड का सेवन कर पानी पीता है और थोड़ी देर बाद तब अपनी समस्याओं को महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला से बताते है।उनके द्वारा किए गए इस सराहनीय पहल की वहां पर आने वाले फरियादियों ने भूरि भूरि प्रशंसा किया।

भाजपा का फोकस बूथ समिति सत्यापन पर, 8 मई तक पूरा करने का लक्ष्य

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे बूथ समिति सत्यापन अभियान के तहत करियप्पा, देवकाली, की बैठकें सिविल लाइन पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई।अयोध्या मंडल की बैठक अशरफी भवन चौराहे के निकट एक सभागार व पूरा मंडल की बैठक ब्लाक सभागार में हुई। बैठकों में अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए आगामी कार्ययोजना पर चर्चा की गई। अयोध्या मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि बूथ समिति का भौतिक सत्यापन संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बूथ समिति का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शक्ति केंद्र स्तर पर बूथ अध्यक्षों की बैठक आयोजित की जाएगी और प्रत्येक बूथ पर समिति के साथ बैठक कर सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी कारणवश निष्क्रिय पदाधिकारियों की सूची तैयार की जाए और उनसे संपर्क कर उन्हें सक्रिय किया जाए। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र के पदाधिकारी लगातार बूथ समितियों के संपर्क में रहें और अभियान को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएं। महानगर अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों को 8 मई तक बूथ समिति सत्यापन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।विभिन्न मंडलों की बैठकों में उपाध्यक्ष तिलकराम मौर्या, अरविन्द सिंह, हरभजन गौड, महामंत्री शैलेन्द्र कोरी, परमानंद मिश्र, शिवेन्द्र सिंह, शिवम्द शुक्ला, राम प्रीत वर्मा, मंडल अध्यक्ष कपिल देव वर्मा, हेमंत जायसवाल, मुकेश तिवारी, दिव्य प्रकाश तिवारी, राम प्रीत वर्मा, स्वपनिल श्रीवास्तव, शशि प्रताप सिंह, आशा गौड, जय प्रकाश श्रीवास्तव, सचिन सरीन, चंदन कसेरा, सहित शक्ति केंद्र संयोजक और बूथ अध्यक्ष उपस्थित रहे।

थाना साइबर क्राइम टीम ने पीडित को 43860 रुपये वापस कराकर किया सराहनीय कार्य

अयोध्या।थाना साइबर क्राइम प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद अरशद व उनकी टीम ने एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज Ack- No- 23111250193601 जिसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक के भाई का फोन हैक करके साइबर ठगी कर लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए 42000 रुपये की धनराशि वापस कराया।जिसमे आरोपी द्वारा खुद को पुलिस अधिकारी बता कर वादी के साथ साइबर ठगी कर लेने के सम्बन्ध मे कार्यवाही करते हुए वादी को 1860 रुपये की धनराशि को वापस कराया गया।अयोध्या पुलिस ने लोगो से अपील किया कि वे साइबर अपराधों से सतर्क रहें, किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या लिंक पर विश्वास न करें और धोखाधड़ी की स्थिति में तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

अनियंत्रित डीसीएम दुकान से भिड़ी,तीन घायल

अयोध्या।जिले के कोतवाली अयोध्या दर्शन नगर बाजार में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया।बताते चले कि डीजे लदी डीसीएम अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसी। यह घटना रात लगभग 1रू00 बजे की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार डीसीएम अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे दुकान में घुस गई।हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।आसपास मौजूद लोगों में घटना के बाद अफरा–तफरी मच गई।घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से नजदीकी ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का नंबर यूपी 45 एफ 1067 है, जिस पर "हैप्पी टांडा" नाम का डीजे लगा हुआ था। यह वाहन फैजाबाद से अकबरपुर की ओर जा रहा था।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।

आईएमए का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम शशांक त्रिपाठी से की शिष्टाचार मुलाकात

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या का एक प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष डॉ. आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में नवागत जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी से शिष्टाचार भेंट करने पहुंचा।इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी श्री त्रिपाठी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत

किया।औपचारिक मुलाकात के दौरान आईएमए पदाधिकारियों ने आईएमए भवन के निर्माण में आ रही विभिन्न समस्याओं से जिलाधिकारी को अवगत कराया। इस मौके पर उन पदाधिकारियों ने इसके शीघ्र से शीघ्र समाधान की मांग की।इस पर जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।इस अवसर पर आईएमए के सचिव डॉ. निशांत सक्सेना, डॉ. आर.के. बनौधा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

रफ्तार का कहर : दो बाइक की आमने–सामने टक्कर दो की मौत

ब्यूरो चीफ : आलोक कुमार श्रीवास्तव

सुल्तानपुर–थाना बल्दीराय क्षेत्र के शारदा सहाय खंड 16 की नहर पी पटरी पूरे चंद्रिका मिश्र बिही गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। सोमवार को दो मोटरसाइकिलों की आमने–सामने हुई जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया। जानकारी के अनुसार, टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं। दुर्घटना में सुरेश चंद्र मिश्रा (45 वर्ष) पुत्र पारसनाथ मिश्रा, निवासी थाना इनायतनगर और राम पटेश्वर पुत्र रघुबीर, निवासी पूरे भवनी अतानगर थाना बल्दीराय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, हादसे में तिलकराज पुत्र पटेश्वर और मानसी पुत्री जगन्नाथ पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन–फानन में अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस हृदयविदारक घटना में एक नौ माह की मासूम बच्ची चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गई, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बनी रही। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार और थाना प्रभारी महेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे से गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है।

थाना महराजगंज क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार – एसपी ग्रामीण

अयोध्या।थाना महराजगंज क्षेत्र मे हुई एक युवक के हत्या मे आरोपी दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।इस संबंध मे एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि सोमवार को इस थाना क्षेत्र के मडना गांव मे मृतक के ऊपर आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था।जिसके चलते गंभीर रुप से घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी।उन्होंने बताया कि इन आरोपियों को थाना महाराजगंज प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह थाना महराजगंज ने थाना क्षेत्र गोसाईगंज के महबूबगंज मे शेरवाघाट मार्ग समय 15.00 बजे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किये गए आरोपियों की पहचान रोहित कुमार यादव पुत्र स्व0 राम कृपाल यादव निवासी ग्राम लायक का पुरवा मजरे मड़ना थाना महराजगंज व विनोद कुमार यादव पुत्र स्व0 रामकृपाल यादव निवासी ग्राम लायक का पुरवा मजरे मड़ना थाना महराजगंज के रुप मे हुई।उक्त आरोपियों को गिरफ्तार करने मे थानाध्यक्ष राजेश सिंह के अलावा उ0नि0 चित्रेश प्रताप सिंह थाना महराजगंज, उ0नि0 आशीष सिंह थाना महराजगंज,हे0का0 महेन्द्र कुमार सरोज थाना महराजगंज,का0 अनुभव सिंह थाना महराजगंज,,रि0का0 हिमांशु यादव थाना महराजगंज व रि0का0 अंकुर चौहान थाना महराजगंज शामिल रहे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी म. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार-पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।